

सभ्रान्त महिलाओं की नकली पीड़ा घातक

भारत के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी की पत्नी सलमा अंसारी ने भारत में महिलाओं की दयनीय स्थिति पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि अच्छा तो यही होता कि समाज में महिलाओं के साथ इतना बुरा व्यवहार करने की अपेक्षा उन्हें पैदा होते ही मार दिया जाता। सलमा जी ने भले ही अपनी भावनाओं का शब्द चयन में अतिरेक कर दिया हो किन्तु उन्होंने अपने मन का यथार्थ व्यक्त कर दिया है। किरण वेदी, मैत्रेयी पुष्पा आदि ने भी शालीन शब्दों में इस प्रश्न को उठाया ही है। मृणाल पांडे कई बार लिख चुकी है। मैंने ज्ञान तत्व में बार बार लिखा है कि भारत की वर्तमान राजनैतिक व्यवस्था शरीफों गरीबों, श्रमजीवियों तथा सामान्य नागरिकों के शोषण के उद्देश्य से अपराधियों, पूंजीपतियों, बुद्धिजीवियों तथा राजनेताओं का मिला-झुला षड़यंत्र है। मैं अब भी अपनी बात पर कायम हूँ। वर्तमान राजनैतिक व्यवस्था का प्रत्येक कदम इन सब गुटों की योजना का हिस्सा होता है। श्रीमति सलमा अंसारी, किरण वेदी, मैत्रेयी पुष्पा मृणाल पाण्डे आदि का नाम इनमें शामिल है। सच्चाई यह है कि ऐसी महिलाओं की संख्या हजारों में है, जो इस शोषण योजना की सक्रिय सदस्य हैं। इन हजारों तथा कथित महिला चिन्तकों में एक भी ऐसी नहीं जो किसी गरीबी रेखा से नीचे के परिवार की सदस्य हो।

सम्पूर्ण भारत में करीब चौबीस करोड़ परिवार रहते हैं। इन चौबीस करोड़ परिवारों में से करीब बीस करोड़ परिवार ऐसे हैं, जो गरीबों श्रमजीवियों तथा सामान्य श्रेणी में माने जा सकते हैं। शेष चार पांच करोड़ परिवार ही सम्पन्न बुद्धिजीवियों या राजनेता की श्रेणी में शामिल हैं। ये चार पांच करोड़ परिवार येन केन प्रकारेण निरंतर ऐसी योजनाएँ बनाते रहते हैं, जो पचीस करोड़ परिवारों की सारी सम्पत्ति सारी राजनैतिक शक्ति इन्हीं चार पांच करोड़ तक सीमित कर दे तथा शेष बीस करोड़ तक इसकी जूठन भी न पहुँच पावे। ये परिवार समाज को वर्गों में बाँटकर वर्ग विद्वेष का ऐसा नाटक करते हैं कि तीन चौथाई परिवार इन एक चौथाई को ही अपना मार्ग दर्शक मान कर इनके मार्गदर्शन में वर्ग विद्वेष में उलझ जावे। समाज आपस में टकराता रहे और ये एक चौथाई परिवार चुपचाप सारा मजा लूटते रहें। इन सबका उद्देश्य न समाज हित है न वर्ग हित। इनका एक मात्र उद्देश्य है स्व परिवार हित। इन हजारों महिलाओं का सिर्फ इतना ही उद्देश्य है जिसे ये नारी हित के आवरण में लपेट कर समाज को दिन रात परोसती रहती हैं। सच्चाई यह है कि नारी हित का आवरण एक मीठा जहर है जो समाज को निरंतर खोखला कर रहा है किन्तु इन सभ्रान्त महिलाओं को इसकी कोई चिन्ता नहीं।

श्रीमती सलमा अंसारी ने बहुत ही तीखे शब्दों में महिला उत्पीड़न का चित्र खींचा है। शब्द चयन ऐसा है कि मुझे भी लिखने को विवश होना पड़ा। मैं सलमा जी से जानना चाहता हूँ कि उन्हें समाज ने कौन सम्मान या लाभ नहीं दिया जिसकी उनके पास योग्यता थी। मैं तो यहाँ तक मानता हूँ कि समाज ने उन्हें उनकी योग्यता से कई गुना अधिक सम्मान और सुविधा सिर्फ इसलिये दे रखी है कि वे उपराष्ट्रपति की पत्नी हैं। उपराष्ट्रपति की पत्नी हो जाने से उनकी सामाजिक योग्यता में कोई ऐसा विस्तार नहीं हो जाता जिसे वे अपना अधिकार समझने लगे। यह तो समाज ने अपना कर्तव्य समझ कर ऐसे प्रमुख लोगों के परिवारों को भी महत्वपूर्ण मानने की परिपाटी डाल ली। हमें दुःख है कि सलमा जी इस परिपाटी को ही अपना अधिकार मानकर समाज को कोसने का नाटक कर रही हैं। क्या उन्होंने कभी यह सोचा कि यदि वास्तव में समाज में उनके व्यंग्य अनुसार जन्मते ही कन्या वध का स्वभाविक चलन होता तो वे आज ऐसे तीखे व्यंग्य करने के लिए कहाँ होती।

ये किरण वेदी, सलमा अंसारी, मैत्रेयी पुष्पा आदि स्वयं के लिए चिन्तित हैं या उन तीन चौथाई परिवारों की महिलाओं के लिए जो आज भी बीस रुपये दैनिक से भी कम पर ही अपना गुजर बसर करती हैं। निश्चित रूप से इनका महिला सशक्तिकरण का रोग उन महिलाओं के लिए तो नहीं ही है। संसद में एक तिहाई महिला आरक्षण हो या आधा या पूरा, इन तीन चौथाई परिवारों की रोजी रोटी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दिन भर मेंहनत करने के बाद भी पति के हाँथों मार खाने वाली नारी को तब और भी ज्यादा कष्ट होता है जब उसके कष्टों के नाम पर सम्पन्न महिलाओं का व्यापार शुरू हो जाता है। बेचारी गरीब महिलायें कष्ट उठाती हैं। इसलिए उनके नाम पर इन सम्पन्न महिलाओं को लाभ के पद दे दिये जायें जिससे शायद उन बेचारी महिलाओं का पेट भर जायेगा। कितना अमानवीय तर्क है? यदि महिला के नाम पर सलमा जी, किरण वेदी मैत्रेयी पुष्पा आदि को लाभकारी पद प्राप्त हो जाये तो उसका सारा लाभ उसके पति, पुत्र, भाई आदि पारिवारिक लोगों को ही मिलना है। आज तक जो भी महिलायें आरक्षण के नाम पर नौकरी में गईं उन्होंने कितना पैसा अपने परिवार के अतिरिक्त महिला कल्याण कोश में जमा किया। कष्टों के वर्णन के लिए पचहत्तर करोड़ कमजोर घरों की महिलाओं के उदाहरण और नौकरी पाने के लिए पच्चीस करोड़ परिवारों की महिलायें आगे आगे। नेता मर गया तो उसकी औरत महिला के नाम पर सबसे आगे। सच्चाई यह है कि इन महिलाओं को न समाज से मतलब है न न्याय से। ये तो येन केन प्रकारेण देश की सुविधाओं का अधिकतम लाभ अपने परिवार के लिए लूट लेना चाहती हैं। इस लूट के लिए यदि इन्हे महिला होने का नाटक भी करना पड़े तो कोई हर्ज नहीं।

ये महिलायें पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था के विरुद्ध दिन रात बोलने का उपक्रम करती रहती हैं। यह पुरुष प्रधान व्यवस्था किसी महिला के लिए वाध्यकारी नहीं। आप स्वतंत्र हैं अपना पति चुनने के लिए। एक पति अपने

से कम योग्य स्त्री के साथ अपना जीवन गुजार देता है और वह पुरुष प्रधान के रूप में रहता है । यदि किसी महिला को पुरुष प्रधान व्यवस्था अमान्य है तो वह क्यों नहीं किसी बहुत कम योग्य लड़के को जीवन साथी चुन लेती है ? उसका निरक्षर पति उसकी सेवा करेगा और वह परिवार का भरण पोषण करेगी। किसने रोका उसे ? विवाह करते समय अपने से ज्यादा योग्य पति चाहिए और विवाह के बाद या तो पति से लड़ झगड़ कर समानता के विवाद पैदा करना या पति के साथ मिलकर समाज में सुविधाओं की छीना-झपटी के लिए महिला आरक्षण, महिला उत्थान जैसे नारे लगाना।

मेरा यह स्पष्ट मत है कि

(1) महिला और पुरुष दो अलग अलग व्यक्तिगत इकाईयां हैं जो कि परिवार के साथ जुड़ते ही व्यक्तिगत इकाई का स्वरूप खो कर परिवार रूपी इकाई में रूपान्तरित हो जाती है। समाज में पुरुष और महिला को वर्ग रूप में खड़ा करना घातक है

(2) महिला अधिकार के लिए संघर्ष करने की परम्परा कुछ महिलाओं द्वारा अपने परिवार के लिए अधिक से अधिक लाभ लूटने की योजना के अतिरिक्त कुछ नहीं।

(3) पुरुष प्रधान व्यवस्था का मूल आधार कम योग्य महिला द्वारा अधिक योग्य पुरुष के साथ विवाह करके परिवार की प्रथा से जुड़ा है, महिला सामानता की पक्षधर महिलाओं को सबसे पहले अपनी लड़कियों को कम योग्य लड़के के साथ जोड़कर पहल करनी चाहिए अधिकांश महिला उत्पीड़न तो यहीं से रूक जायेगा।

इन सभ्रान्त महिलाओं का मुख्य आरोप है कि समाज में महिलाओं पर बलात्कार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। यह बात सच भी हैं। विचारणीय प्रश्न यह है कि बलात्कार बढ़ने के लिये समाज दोषी है या नई राजनैतिक व्यवस्था ? सब लोग कहते हैं कि नई राजनैतिक व्यवस्था के परिणाम स्वरूप महिलाओं में कई गुना ज्यादा जागृति आई है। जब महिलाओं में पुराने समय की अपेक्षा जागृति आई है तो बलात्कार बढ़ क्यों रहें हैं ? जागृति और बलात्कार का कोई संबंध है क्या यह एक गंभीर विषय है। यदि किसी वस्तु की मांग बढ़ेगी और पूर्ति घटेगी तो भ्रष्टाचार होना निश्चित है। नई राजनैतिक व्यवस्था ने महिला पुरुष के बीच के संबंधों की पूर्व प्रचलित व्यवस्था के साथ अनावश्यक छेड़ छड़ की। इन्होंने महिला जागृति के नाम पर महिला और पुरुष के बीच की दूरियाँ कम कर दी। स्वाभाविक ही था कि दूरी कम होने से इच्छायें अधिक पैदा होने लगी और सैक्स की माँग बढ़ी। इन नई व्यवस्था वालों ने वैश्यावृत्ति पर रोक लगाकर पूर्ति घटा दी। इनसे कौन पूछे कि बलात्कार वृद्धि का मूल कारण तो तुम जैसी महिलायें ही हो जो स्त्री पुरुष के बीच की दूरी भी घटाना चाहती हो और वैश्यावृत्ति भी रोकना चाहती हो या जो असंभव है। बलात्कार का बढ़ना नई व्यवस्था का स्वाभाविक परिणाम है।

मैं सलमा जी और किरण वेदी से पूछना चाहता हूँ कि महिला पुरुष के बीच दूरी भी घटे, वैश्यावृत्ति को भी रोक दिया जाय और बलात्कार भी न हो इसका उनके पास क्या उपाय है ? तीनों का यदि एक साथ कोई समाधान है तो सिर्फ एक ही है कि सारे पुरुष समाज को एक ऐसा इंजैक्शन लगा दिया जाय कि उनकी स्वाभाविक काम इच्छा ही पूरी तरह समाप्त हो जावे । फिर नपुंसक पुरुषों से महिलाओं को कोई खतरा ही नहीं रहेगा ।

मैं सलमा जी, किरण वेदी आदि से निवेदन करता हूँ कि उन्हें और उनके परिवार को समाज ने जो कुछ सम्मान और सुविधा दी है उतने से ही संतोष करके दूसरे परिवारों को आगे आने दे । यदि वे पति को योग्यता के आधार पर और स्वयं महिला के नाम पर छीना झपटी करेगी तो इस समाज के साथ अन्याय करेगी । आज भले ही उन्हें इसका लाभ मिल जावे परन्तु इतिहास कलंकित ही होगा जो उनके लिए ठीक नहीं होगा । अपने राजनैतिक स्वार्थ के लिए महिला और पुरुष को वर्ग के रूप में खड़ा मत करिये । समाज के सामाजिक संबंधों के साथ छेड़ छड़ न करे तो समाज अनेक समस्याएँ अपने आप सुलझा लेगा ।

प्रश्नोत्तर

1 आचार्य पंकज, राष्ट्रीय अध्यक्ष व्यवस्था परिवर्तन मंच, रिषिकेश, उत्तरांचल

सुझाव—जनसत्ता तीन अक्टूबर में छपे समाचार के अनुसार राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलौत ने राजस्थान की ग्राम पंचायतों को पांच विभागों के विधायी अधिकार सौंपने की घोषणा की है । श्री गहलौत भारत के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने यह पहल की है किन्तु आपने मनमोहन सिंह, चिदम्बरम, नरेन्द्र मोदी, नीतिश कुमार आदि के साथ अशोक गहलौत का नाम नहीं जोड़ा । श्री गहलौत गांधीवादी विचारों पर कामकर रहे हैं । मेरा सुझाव है कि आपने जो तीन श्रेणियाँ बनाई हैं उनमें गहलौत जी को पहली श्रेणी में रखें ।

उत्तर—जनसत्ता में छपे समाचार के अनुसार श्री अशोक गहलौत ने राजस्थान की पंचायतों को कोई एक भी विधायी अधिकार नहीं दिया है । आप जानते हैं कि भाजपा नीतियों के आधार पर केन्द्रीयकरण की पक्षधर है और कांग्रेस विकेन्द्रीयकरण की । पिछली वसुन्धरा सरकार ने पंचायतों को प्राप्त उन्तीस कार्यपालिक अधिकार धीरे-धीरे वापस कर लिये थे । गहलौत सरकार ने उनमें से पांच विभाग फिर से पंचायतों को देने की घोषणा की है । ये पंचायतों को प्राप्त होने वाले विधायी अधिकार नहीं हैं । आज तक किसी भी प्रदेश में कोई भी विधायी अधिकार पंचायतों को नहीं दिया गया है । यहाँ तक कि मध्यप्रदेश के मुख्य मंत्री दिग्वीजय सिंह ने भी जो पंचायती राज्य के प्रमुख समर्थक माने गये, उन्होंने भी यह पहल नहीं की फिर भी श्री गहलौत ने

भाजपा सरकार में वापस किये गये अधिकार पंचायतों को वापस करने की पहल करके अच्छा काम किया है। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ।

जो तीन प्रकार की सूचियाँ बनी है उसका मुख्य आधार भ्रष्टाचार है । भ्रष्टाचार के मामले में अशोक गहलौत जी भी ठीक माने जाते है किन्तु अभी नरेन्द्र मोदी,मनमोहन सिंह, नितिश कुमार की तुलना में उन्हे कुछ और समय बिताना होगा। हो सकता है कि मेरी जानकारी अधूरी हो । भविष्य में इस सूची में जब संशोधन होगा तब अवश्य ही ध्यान रखा जायेगा।

2 श्री चन्द्र मौलेश्वर प्रसाद, अलवल, सिकन्दराबाद, आन्ध्र इमेल से

प्रश्न-15 फरवरी के अंक में आपने विनायक सेन प्रकरण में कुछ बातें कही हैं जो चिन्तनीय है। आपने कहा कि अरुन्धति के विचारों पर कानूनी कार्यवाही नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। हम किस गुमान में ऐसी अभिव्यक्तियों को बढ़ावा दे रहे हैं जो देश को तोड़ने की नींव डाल रही है। अंग्रेजी में कहावत है-निप इट इन द बड। यदि हम बीज रूप में ही इसका समाधान निकाल ले तो पेड़ को काटने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। नक्सली हो या पीयूसीएल। वे नक्सली के मरने पर शोर मचायेंगे पर मासूम लोग बस में मारे गये या पुलिस बल को बम से उड़ाया गया तो इन्हे सांप सुघ जायेगा वेंगल राव जब मुखमंत्री थे तब इन पर सख्ती से काम किया गया था और उस समय इनका सफाया कर दिया था। उसके बाद की सरकारों की ढुलमुल नीति के कारण बात यहाँ तक आ पहुँची है। विनायक प्रकरण का एक कोण यह भी है कि ईसाइयत का प्रसार हो रहा था तभी तो विदेशी भी आकर उनसे सहानुभूति जता रहे थे । ऐसे कई कोण हैं जिन्हे ध्यान में रखना होगा।

कश्मीर के बारे में आज अलगाववादी इसलिए जोर शोर से बोल रहे हैं क्योंकि 1948 में उसे नहीं कुचला गया । रही कश्मीरी पंडितों की बात तो जब आठ दस प्रतिशत मुश्लमान देश की राजनीति को बदल सकते हैं तो इन पंडितों ने यह कार्य क्यों नहीं किया। इसलिए कि उनके साथ सरकार नहीं थी तभी तो उन्हे अपने जन्मस्थल को छोड़कर भागना पड़ा। यदि आज भी देश के लोगों को छूट मिले कि वे कश्मीर में बस सकते हैं तो शायद तस्वीर कुछ और होगी। अब तो चीन भी साफ कह रहा है कि युद्ध ही किसी चीज का हल है और भारत में हमारा नमक खाते हुए भी देश का झंडा पकड़ने से लोग कतरा रहें हैं जबकि इन्ही लोगों को यह दिखाई नहीं देता कि चीन ने कश्मीर के बड़े भाग को कब्जाया है!!! वहाँ के नेता आज भी रियासत के ख्वाब देख रहे हैं तभी तो वे कश्मीरीयत की बात करते हैं भारतीयता की बात नहीं करते।

इस अंक में मेरे पत्र कि उत्तर में आपने कुछ मुद्दे उठाए हैं। आपने कहा कि किरण बेदी और स्वामी रामदेव ने समाज को कोई ऐसा मार्ग नहीं दिखाया

है। यहीं सोच का अंतर है, बुद्धिजीवी और राजनीति में। बुद्धिजीवी ईमानदार भले ही हो वह राजनीति नहीं कर सकता। यह काम राजनेता का है जो मार्ग सुझा सकते हैं और उन्हें लागू भी कर सकते हैं। हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ बुद्धिजीवी आज प्रधानमंत्री हैं पर उनकी राजनीति पर पकड़ नहीं है, इसलिए वे अपने आप को असहाय पाते हैं। जिस व्यक्ति ने देश को आर्थिक दलदल से निकाला था आज वही राजनीतिक दलदल में फसां हैं, इससे अधिक दुर्भाग्य देश का क्या होगा। आज जब बाहुबली अपराधिक पृष्ठभूमि के लोग संसद में हैं और कानून बनाने की प्रक्रिया उनके हाथ में है, तो कानूनदां भी कुछ नहीं कर सकता। इसका समाधान संसद ही निकाल सकती है ।

आपने शिक्षित और भ्रष्टाचार के कुछ आकड़े देते हुए यह सिद्ध किया है कि शिक्षा के साथ भ्रष्टाचार भी बढ़ा है। शिक्षित और पढ़े-लिखे में अंतर हैं। हम शिक्षित उसे कहेंगे जो अच्छे संस्कार और आचार के साथ ज्ञान पाता है। आज शिक्षा के नाम पर संस्कार और आचार का पठन शून्य है। तो फिर, अच्छे नागरिक कहा से पैदा होंगे ?

उत्तर- आपका सुझाव है कि जहरीले फल देने वाले बीज को ही नष्ट कर देना सबसे आसान काम है। आप यह सोचिये कि बीज अच्छा भी हो सकता है और जहरीला भी। कौन सा बीज जहरीला है इसका निर्णय कौन करेगा ? समाज या राज्य ? यदि राज्य को निर्णय का अन्तिम अधिकार दे दिया गया तो उसके घातक परिणाम होंगे। आज जब अरुन्धतीराय या गिलानी की बात है तो आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीमा लगाने की बात अच्छी लग रही है किन्तु यदि परिस्थियाँ इसके विपरीत हुईं तब हमें कई गुना ज्यादा गुलामी झेलनी पड़ सकती है। हम इंदिरा जी के आपात काल को भूले नहीं हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि हम गलत विचारों का मुकाबला सही विचारों से ही करें न कि विचारों को कानून से रोककर ।

विनायक सेन प्रकरण को इसाइयत के साथ जोड़ना ठीक नहीं। यूरोपीय युनियन के लोग इसाई और हिन्दू के नाम पर नहीं आये थे। वे आये थे समाजवाद और मानवाधिकार के नाम पर। जिस तरह विदेशी शक्तियों ने तथा उनसे पुरस्कार पाने वालों ने दबाव बनाया था। उससे स्पष्ट दिखने लगा था कि हमारी न्यायपालिका दबाव नहीं झेल पायगी। जिस ताम झाम के साथ हल्ला करके विदेशी शक्तियाँ न्यायलय में आकर बैठीं वह तो एक प्रकार का खुला दबाव ही था। विदेशी शक्तियों द्वारा पुरस्कार प्राप्त सभी लोगों ने एक स्वर में विनायक सेन के पक्ष में हस्ताक्षर भी किये और आवाज भी उठाई। इस हस्ताक्षर अभियान से स्पष्ट हुआ कि ये विदेशी पुरस्कार लेना और देना भी किसी गुलामी से ज्यादा कुछ नहीं। पुरस्कार लेने का संकेत है कि आप कहीं न कहीं बंध रहे हैं । फिर भी हमारे न्यायालयों ने सारे दबाव के बाद भी निर्णय देकर एक मिसाल कायम कर दी है। विदेशी हस्तक्षेप कर्ता शक्तियाँ तो शर्मिन्दा हैं ही किन्तु हमारे देश में उछल कूद कर रहे मानवाधिकार

कार्यकर्ता और विदेशी सम्मान पाये हुए हस्ताक्षर कर्ताओं की तो बोलती ही बन्द है।

आप हर मामले में कुचलने की बात कह रहे हैं जो जो ठीक नहीं। कुचलना अन्तिम समाधान है, पहला नहीं। नक्सलवादियों के पक्ष में बोलने वालों को भी कुचल दे और कश्मीर में आवाज उठाने वालों को भी। चीन हमेशा ऐसी भाषा बोलता रहा किन्तु अब उसने भी अपनी भाषा सुधारनी शुरू की है। हम दुनियाँ में अकेले नहीं हैं बल्कि दुनियाँ के एक भाग मात्र हैं। आप बार बार कश्मीर जाकर बसने की बात कर रहे हैं क्यों नहीं आप छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के अबूझभाड क्षेत्र में बस जाते। कौन रोक रहा है आपको ?

यह हमारे देश का सौभाग्य है कि हमारा प्रधानमंत्री राजनीतिज्ञ नहीं हैं। यदि वे राजनैतिक दांव पेंच के जानकार होते तो वे लोकप्रिय हो जाते भले ही देश का कुछ भी होता। हमारे बिपक्ष के नेता अडवाणी जी ने बड़ी शान से कहा कि स्वतंत्रता के बाद मनमोहन सिंह सबसे कमजोर प्रधानमंत्री हैं। मेरे विचार में यह हमारे लिए गर्व की बात है, शर्म की नहीं। हम किसी तानाशाह देश की चर्चा नहीं कर रहे जहाँ मजबूत प्रधानमंत्री की जरूरत हो। हमने साठ वर्षों के नेहरू परिवार के शासन में मजबूत प्रधानमंत्री देखे हैं जो न मंत्रिमंडल की परवाह करते थे न पार्टी की। अडवाणी जी ने ऐसे प्रधानमंत्री की तारीफ करके अपने स्वभाव का परिचय दिया है जिन्हे लौह पुरुष कहे जाने पर गर्व होता है। प्रधानमंत्री प्रत्येक मंत्री से तो उपर होता है किन्तु मंत्रिमंडल से उसे नीचे ही रहना चाहिए। उसे पार्टी से भी नीचे रहना पड़ता है। न अडवाणी जी ने कभी पार्टी की परवाह की न नेहरू ने और न ही इन्दिरा ने। मेरे विचार में यह प्रवृत्ति घातक है। मंत्रिमंडल का निर्णय सामूहिक होता है। मनमोहन सिंह जी ने साठ वर्षों में पहली बार लोकतंत्र को ठीक से समझा है। सामूहिक जिम्मेवारी से देश चलाना बहुत कठिन काम है क्योंकि ऐसी स्थिति में कई बार न चाहते हुए भी अपने अहम को दबाना पड़ता है। कई बार तो यही लोकतंत्र आपको अडवाणी सरीखे लौह पुरुष के ताने सुनने को भी मजबूर कर देता है। मेरा स्पष्ट मत है कि भारत के लिए लौह पुरुष की जरूरत न होकर समाजवादी प्रधानमंत्री अधिक अच्छा होगा। हमने लौह पुरुष का जमाना देख लिया। लौह पुरुषो ने देश को जितना नुकसान पहुचाया है वह बहुत है। अब तो भारत को ऐसे लौह विचारों से मुक्ति चाहिए। मनमोहन सिंह जी ने यह खतरा उठाया है। उन्होंने अपनी बदनामी उठाकर भी लोकतंत्र तथा सामूहिक नेतृत्व की नयी प्रणाली विकसित की है। अडवाणी जी ने अपने भाषणों में मनमोहन सिंह को दया का पात्र बताया है। मुझे दुख होता है कि पंडित नेहरू, इन्दिरा गाँधी, राजीव गाँधी आदि तो उनकी नजर में प्रशंसा के पात्र हैं और मनमोहन सिंह दया के पात्र। आप चाहे जो सोचते हो किन्तु मेरा विचार है कि किसी सुशासक तानाशाह की अपेक्षा लोक तांत्रिक कमजोर प्रशासक कई गुना अच्छा होता है। नेहरू, इन्दिरा गाँधी आदि सुशासक थे या कुशासक यह तो अडवाणी जी बता सकते हैं किन्तु मनमाने निर्णय लेने के

लिए जीवन भर विख्यात रहे। मनमोहन सिंह ने जो भी निर्णय किये उनमे एक भी मनमाना नहीं था चाहे वह निर्णय अच्छा रहा हो या बुरा। भाजपा को नेहरू परिवार में गुण दिखने लगे हैं और मेरी साठ वर्षों से धारणा रही है कि जब तक देश से परिवारवाद समाप्त नहीं होगा तब तक भारत की समस्याओं का समाधान सम्भव नहीं।

3 श्री छवील सिंह सिसोदिया, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश

प्रश्न-आपने ज्ञान तत्व में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की प्रशंसा करके हम सबको आश्चर्य चकित किया है जो प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार नहीं रोक सकता, मंहगाई नहीं रोक सकता विदेशो से काला धन वापस नहीं ला सकता ऐसे निकम्मे प्रधानमंत्री का हम क्या करे। संसद का पूरा सत्र जे.पी.सी की मांग की भेट चढ़ गया किन्तु प्रधानमंत्री ने माँग नहीं मानी। अब बड़ी मुश्किल से लाचार होकर मानी। जे.पी.सी. की माँग न्यायोचित थी किन्तु प्रधानमंत्री अड़े रहे। इनसे तो अच्छे सोमनाथ चटर्जी थे जिन्होंने राइट टू रि कॉल का समर्थन किया था।

उत्तर-ज्ञान तत्व 217 में लिखे मेरे लेख पर गंभीर प्रश्न उठाने वाले आप अकेले नहीं हैं। मनोज दुबलिस जी मेरठ ने तो और भी आगे जाकर लिखा है कि ऐसे प्रधानमंत्री को इमानदार कहना, इमानदारी का ही अपमान है। अन्य साथियों ने भी अपने अपने तरीके से विरोध प्रकट किया है। सिर्फ विस्फोट डाट काम के संजय तिवारी जी ने अपने बेवसाइट पर एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने ठीक दिशा ली अन्यथा मैं तो ऐसा विचार रखकर स्वयं को नितान्त अकेला ही महसूस कर रहा था।

बिल्कुल अकेला होने के बाद भी मैं आज तक अपने विचार पर कायम हूँ। मैं अब भी चाहता हूँ कि इस मुद्दे पर खुला विचार मंथन हो। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर आरोप है कि वे कमजोर प्रधानमंत्री हैं। मेरे विचार मे आरोप सच है। अब तक भारत मे जो भी प्रधानमंत्री हुए वे सब कही न कही मनमोहन सिंह की अपेक्षा अधिक मजबूत थे। प्रेस कांफ्रेंस में उन्होंने दो बातें कही (1) वे इतने बुरे नहीं हैं जितना प्रचारित हो रहा है (2) उन्होंने कई गलतियाँ भी की हैं किन्तु गलतियों से अधिक अच्छे काम किये हैं। मैं जानता हूँ कि मनमोहन सिंह न बुरे आदमी हैं न उन्होंने गलतियाँ की हैं। आज तक किसी प्रधानमंत्री ने गलती करने के बाद भी गलती स्वीकार नहीं की क्योंकि वे मजबूत प्रधानमंत्री थे। पंडित नेहरू और इन्दिरा गांधी जिनकी तारीफ लालकृष्ण अडवाणी जी ने मजबूत प्रधानमंत्री के रूप में की हैं, उन्होंने कश्मीर का मसला उलझाकर या अपातकाल लगाने के बाद भी कभी गलती नहीं मानी क्योंकि वे मजबूत प्रधानमंत्री थे। दूसरी ओर हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी बिना गलती किये, गलती मान रहे हैं। सिद्ध होता है कि वे वास्तव में अब तक के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री हैं।

दूसरा आरोप है कि उन्हें राजनीति नहीं आती। आज कल राजनीति का अर्थ कुटनीति ही माना जाता है यह बात भी पूरी तरह सच है। मनमोहन जी कुटनीति के मामले में कमजोर प्रधानमंत्री है। जैसे तो स्वतंत्रता के बाद कुटनीति रूपी राजनीति का केन्द्र तो नेहरू परिवार ही रहा है। लाल बहादुर शास्त्री, मुरार जी देसाई, विश्वनाथ प्रताप सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी आदि नेहरू परिवार की कुटनीति के सामने हमेशा पराजित रहे। मनमोन सिंह तो राजनीति रूपी कुटनीति में शून्य ही माने जाते हैं।

हमें सबसे पहले यह विचार करना होगा कि मजबूती और कुटनीति में पारंगत होना हमारे भारत के प्रधानमंत्री का गुण मानना चाहिए कि दुर्गुण। स्पष्ट सिद्धान्त है कि शासन के लिए ये दोनों गुण माने जाते हैं और व्यवस्था के लिए दुर्गुण क्योंकि कुटनीति हमेशा ही शासन में सहायक होती है और व्यवस्था में घातक। नेहरू परिवार में हमेशा शासक की भावना रही है। अडवाणी जी ने भी सत्ता की ओर दौड़ में प्रतिस्पर्धा की है। कभी शासन को व्यवस्था के रूप में किसी ने नहीं समझा। अटल जी ने इस दिशा में बढ़ने का प्रयास किया तो किनारे कर दिये गये। पहली बार मनमोहन सिंह ने स्वयं को शासक न समझकर व्यवस्थापक रूप में माना। शासन हमेशा दूसरे पर होता है और व्यवस्था हमेशा अपने के बीच होती है। शासन के लिए मजबूती भी आवश्यक है और कुटनीति भी। मैं आज तक नहीं समझ सका कि अपने के बीच क्यों मजबूती आवश्यक है क्यों कुटनीति। विदेश संबंधों के मामलों में तो मजबूती और कुटनीति आवश्यक होती है किन्तु हमारे आन्तरिक मामलों में यह प्रवृत्ति घातक है। साठ वर्षों के शासन काल में नेहरू परिवार ने हमेशा शासक और शासित के भाव को मजबूत किया। परिणाम स्वरूप भारतीय जनमानस गुलाम मानसिकता का अभ्यस्त हो गया। उसे एक मजबूत शासक चाहिए। दूसरे के लिए तो चाहिए ही, अपने लिए भी चाहिए। यदि कोई प्रधानमंत्री उन्हें व्यवस्था में भागीदारी देता है तो उसे अव्यवस्था का डर सताने लगता है। वह उसको कमजोर कहकर उसके गुण को ही अवगुण बताना शुरू कर देता है जैसा कि आज हम देख रहे हैं।

मनमोहन सिंह पर तीसरा आरोप है कि उन्होंने भ्रष्टाचार रोकने के लिए कुछ नहीं किया। मेरे विचार में यह आरोप पूरी तरह उल्टा है। स्वतंत्रता के बाद पहली बार हुआ है कि उतने बड़े बड़े घपले उजागर हुए। हर आदमी मानता है कि सन सैतालीस से लेकर आज तक निरंतर भ्रष्टाचार बढ़ता रहा है। निरंतर भ्रष्टाचार बढ़ने का कारण यह था कि अधिकांश भ्रष्टाचारों में सत्ता का समर्थन था और हर शासक कुटनीति का सधा खिलाड़ी था। राजीव गांधी पर भ्रष्टाचार का आरोप आज तक लटक रहा है और आश्चर्य की बात है कि ऐसे गंभीर आरोप के बाद भी वह परिवार सीना तानकर सत्ता संघर्ष में शामिल है। सम्पूर्ण भारत में यह मान लिया गया है कि सत्ता और भ्रष्टाचार के बीच चोली दामन का संबंध है। यदि सत्ता का संबंध रहेगा तो भ्रष्टाचार कभी भी कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। पहली बार राजनेताओं तथा नौकर शाहों के बीच यह नया संदेश जाना शुरू हुआ है कि भ्रष्टाचार का छिपना अब उतना

असान नही। मेरे विचार में इस संदेश का एक ही आधार है कि प्रधानमंत्री न स्वयं भ्रष्ट हैं न स्वयं शासक है। वह तो व्यवस्था प्रमुख पात्र है। यदि व्यवस्था में कोई फंसा तो उसे प्रधानमंत्री की ओर से कोई सुरक्षा नहीं और व्यवस्था से कोई बच गया तो प्रधानमंत्री की ओर से उसे फसाने की कोई पहल नहीं। यही कारण है कि साठ पैसठ वर्षों से निरंतर बढ़ते जा रहे भ्रष्टाचार की एक एक परत खुलनी शुरू हुई है। अब तो न्यायपालिका के भी भ्रष्टाचार उजागर होने लगे हैं अब तो बड़ी बड़ी वैज्ञानिक शोध संस्थाएँ भी सफाई देती फिर रही है। भ्रष्टाचार पर स्थाई चोट शुरू हो गई है और वह भी किसी प्रधानमंत्री की सक्रियता का परिणाम न होकर किसी प्रधानमंत्री द्वारा शासन व्यवस्था में बदलाव का परिणाम है।

मनमोहन सिंह जी पर चौथा आरोप है कि उन्होंने विदेशों में जमा खरबों का काला धन वापस लाने की कोई ठोस पहल नहीं की। यह आरोप पूरी तरह असत्य है। भारत से जो भी काला धन विदेशों में जाकर चोरी से जमा हुआ, उसके विदेश जाने की मात्रा उन प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल की है जो मजबूत प्रधानमंत्री थे। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ऐसा धन विदेश जाने की गति घटी है। आश्चर्य है कि पिछले प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में चोरी होती रही। उन्हें मजबूत प्रधानमंत्री कहा जा रहा है और वर्तमान प्रधानमंत्री पर आरोप है कि वे उन चोरों के न नाम उजागर कर रहे हैं न ही माल पकड़कर ला रहे हैं। आश्चर्य यह है कि यह आरोप लगाने में वे लोग आगे आगे हैं जिनके स्वयं के मजबूत शासन काल में भी यह काला धन विदेश जाता रहा। वे मजबूत लोग एक कमजोर प्रधानमंत्री से प्रश्न कर रहे हैं कि आपने अब तक कुछ नहीं किया। जो न्यायपालिका इस समय काले धन के मामले में इतनी सक्रिय है वही न्यायपालिका साठ वर्षों से क्या कर रही थी जब काला धन चोरी से जा रहा था ? स्पष्ट है कि उस समय न्यायपालिका भी मजबूत प्रधानमंत्री होने के कारण दबी हुई थी जो अब मनमोहन सिंह के कार्यकाल में मजबूती से कदम उठा पा रही है।

मुझे डर है कि बड़ी मुश्किल से साठ पैसठ वर्ष बाद हमारा भारत का लोकतंत्र नेहरू परिवार द्वारा स्थापित पालित पोषित शासक शासित वाली व्यवस्था से निकल रहा है। अब न्यायपालिका मजबूत कदम उठा पा रही है। अब मंत्री मंडल के सदस्य खुले आम अपने विचार व्यक्त करने लगे हैं। अब देश का आम नागरिक भ्रष्टाचार पर खुली चर्चा करने लगा है। कहीं ऐसा न हो जावे कि यह सारा प्रयत्न हमारी ना समझी से असफल हो जावे और भारत फिर से नेहरू परिवार स्थापित मजबूत प्रधानमंत्री के कूटनीतिक राजनैतिक जाल में फस जावे। नेहरू परिवार के पास साठ वर्षों से लगातार एक बुना हुआ कूटनीतिक जाल है। उस जाल से न चन्द्रशेखर बच पाए न चरण सिंह । अब उस जाल की लालच में अडवाणी जी फंस रहे हैं । अडवाणी जी ने जिस तीव्रता से सोनिया जी से क्षमा याचना की वह तीव्रता एक खतरनाक दिशा को प्रकट करती है।

मेरी हार्दिक इच्छा है कि हम प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की भूलों की तरह इशारा भी करे और उन्हें सलाह भी दे । आवश्यकता होने पर उनकी समीक्षा भी करे किन्तु सलाह और समीक्षा के नाम पर आलोचना का खेल बन्द कर दे। वर्तमान समय में मनमोहन सिंह की आलोचना दो समूहों को ज्यादा पसंद आ रही है जिनमे एक है नेहरू परिवार, दिग्विजय सिंह तथा उनकी चौकड़ी और दूसरे है अडवाणी, सुषमा स्वराज की टीम। पिछले साठ वर्षों से इन दोनों का सत्ता संघर्ष हम देखते रहे है जिसमें नेहरू परिवार हमेशा ही मजबूत रहा। अब भी वही खतरा है कि घूम फिरकर भारत के भाग्य की चोटी नेहरू परिवार के हाथ आ जायेगी । हमे अब भी सतर्क होना है।

मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप अब कम से कम भारत के साथ कोई खिलवाड़ न करे । हम सबसे पहले आश्वस्त हो कि भारत नेहरू परिवार की राजनैतिक छाया से पूरी तरह मुक्त हो चुका है । उसके बाद हम तय करे कि हमे कौन सी व्यवस्था पसन्द है । यदि हमे मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए तो नरेन्द्र मोदी अन्यथा नितिश कुमार। जब तक ऐसी आश्वस्ति न हो जाये तब तक हम किसी भी तरह मनमोहन सिंह को कमजोर न होने दे। देश को बचाना है तो हमे खिलवाड़ बन्द करना ही चाहिए । मेरा भाजपा से आग्रह है कि वह लालच में फंस कर नेहरू परिवार को मजबूत करने का राष्ट्र घातक कदम न उठावे। मेरा आपसे भी निवेदन है कि आप ऐसी कूटनीतिक चालो को समझने की कोशिश करे, जिनमे देश साठ वर्षों से फसा हुआ है ।

मैने पिछले लेख में मनमोहन सिंह जी को त्यागपत्र देने की सलाह दी थी । मेरा आशय यह था कि मनमोहन सिंह का बना रहना देश हित में है किन्तु अब ऐसा संभव नही दिखता। इसलिए मनमोहन सिंह के व्यक्तिगतहित में है कि वे त्यागपत्र दे दे। मेरे विचार से यदि उन्होने त्यागपत्र नही दिया तो उनकी शहादत स्पष्ट है। निर्णय करना है कि वे देश हित में शहीद हो जाये अथवा चुपचाप नेहरू परिवार के बीच से हटकर स्वयं को बचा ले । मनमोहन सिंह जी ने शहीद होना ही ठीक समझा है। अब मेरी आपको सलाह है कि आप सोच समझकर निर्णय लें।

मनमोहन सिंह की प्रेस कांफ्रेस

मनमोहन सिंह जी ने प्रेस को संबोधित किया। उनका स्वर बुझा हुआ था। आंखे नम थी। उनके हर वाक्य से ऐसा आभास होता था कि वे वास्तव में दुखी मन से उत्तर दे रहे है।

उन्होने प्रश्नो के उत्तर में कहा कि उनकी कई प्रकार की मजबूरियाँ रही जिनके कारण वे ठोस निर्णय नहीं ले पायें। गठबंधन सरकार चलाने के लिए न चाहते हुए भी समझौते करने पड़ते हैं जो मैंने भी किये। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनसे भी कई गलतियाँ हुई है। किन्तु इन सबके बावजूद वे उतने बुरे नहीं जितने प्रचारित किये गये है। मनमोहन सिंह जी ने कई प्रश्नो के उत्तर भी दिये जिनमें निराशा का भाव अधिक था, उत्साह कम।

पूरी प्रेस कांफ्रेंस के बाद मुझे ऐसा लगा कि मनमोहन सिंह हृदय से दुखी और निराश थे और वे दिल से त्याग पत्र के पक्ष में हैं। किन्तु सोनिया जी उन्हें तब तक बनाये रखना चाहती हैं जब तक उनकी और छीछालेदर न हो जावे। सोनिया जी राहुल के लिये कोई खतरा मोल नहीं ले सकती। यही कारण है कि मनमोहन सिंह जी को त्याग पत्र से भी रोक कर रखा गया है।

राजनीति में कब क्या हो जावे यह पता नहीं चलता। भाजपा का हर नेता एक ओर तो मनमोहन सिंह को कमजोर और डमी प्रधानमंत्री कहता है तो दूसरी ओर वह कांग्रेस पार्टी या सोनिया राहुल को बचाकर मनमोहन सिंह की आलोचना करता है जबकि वे रिमोट कंट्रोल से ज्यादा कुछ नहीं। आश्चर्य तो तब हुआ जब भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने मनमोहन सिंह की तुलना में पण्डित नेहरू, इन्दिरा गांधी तथा राजीव गांधी तक की भरपूर प्रशंसा कर दी। पण्डित नेहरू का तो उन्होंने नाम तक लिया। अब भाजपा को नेहरू परिवार में सारी अच्छाइयां नजर आने लगी हैं। प्रधानमंत्री ने प्रेस कांफ्रेंस में एक प्रश्न के उत्तर में खुलासा किया कि भाजपा गुजरात के एक मंत्री के खिलाफ हुई कानूनी कार्यवाही के बदले ऐसी आक्रामक है। मुझे भी लगता है कि भाजपा द्वारा प्रधानमंत्री के खिलाफ एकतरफा मोर्चा खोलने का यह कारण हो सकता है अन्यथा जीवन भर नेहरू इन्दिरा परिवार को जी भर कर कोसने वाली भाजपा एकाएक उस परिवार की सहायक कैसे बन जाती।

मनमोहन सिंह जी की सबसे बड़ी गलती तो यही रही कि उन्होंने कभी किसी गलत कार्य से समझौता नहीं किया। उन्होंने न तो किसी गलत कार्य का सीमा से अधिक विरोध किया और न समर्थन। उन्होंने सब कुछ एक व्यवस्था के अनुसार चलने दिया। वे भूल गये कि राजनीति में कूटनीति का भी बहुत महत्व होता है। आज वे एक कूटनीतिक षडयंत्र के शिकार हैं जिसके एक पक्ष में खड़ा है नेहरू परिवार और उनकी चौकड़ी तो दूसरे पक्ष में ताल ठोक रहे हैं आडवाणी और उनकी चौकड़ी।

सच्चाई चाहे जो हो किन्तु इतना तो स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह जी चक्रव्यूह में पूरी तरह फंसे गये हैं और कोई चमत्कार ही उन्हें बचा सकता है अन्यथा अब राहुल गांधी और आडवाणी के बीच जंग होगी और इसमें राहुल गांधी का मार्ग आसान दिख रहा है।

नोट- पिछले अंक में मैंने सभी पाठकों से निवेदन किया था कि वे कम से कम दस-दस नये गंभीर पाठकों के नाम ज्ञान तत्व को भेजे। इस संबंध में श्री सोमकांत शर्मा दुर्ग से दस नये नाम प्राप्त हुए हैं। तीन नाम महेन्द्र प्रसाद जी जोधपुर राजस्थान तथा तीस नाम श्री जे० पी० सिंह विल्थरा रोड बलिया ३० प्र० से प्राप्त हुए हैं। अन्य पाठकों से नये प्राप्त करने की प्रतीक्षा है।

नोट दो-श्री पंकज गोयल तथा श्री मति प्रीति गोयल ए-196 से0-22 नोएडा गौतमबुद्ध नगर 30 प्र0 ने ज्ञान यज्ञ परिवार ट्रस्ट मे सम्मिलित होकर दो हजार रूपया मासिक दान स्वरूप देने की सूचना दी हैं। हम श्री गोयल तथा श्री मति गोयल का धन्यवाद देते है कि वे ज्ञान यज्ञ परिवार ट्रस्ट के दाता सदस्य के रूप मे पंजीकृत हुए हैं। अब ट्रस्ट मे ऐसे दाता सदस्यों की सूची बढ़कर सात हो गई है।

सूचना-

लोकस्वराज्य संघ तथा ज्ञान यज्ञ परिवार की मिली जुली बैठक 27 मार्च को उज्जैन में पौराणिक जी के निवास पर होनी तय हुयी है। आपसे निवेदन है कि आप आने की कृपा करें। पौराणीक जी का फोन नम्बर 09406626456 है।